Nav Jyoti, Vol. 5, No. 10, January-June 2017 ISSN : 2249-7331

21वीं सदी में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की चुनौतियाँ

डॉ0 निशा अग्रवाल*

सारांश

विकसित नई कार्य संस्कृति के तहत भारत की वैधानिक तथा तकनीकी क्षेत्र की क्षमताओं को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भरपूर सराहना मिल रही है। सारा विश्व आज भारतीयों के ज्ञान समाज के निर्माण में किये जाने वाले योगदान से अभीभूत है। आजादी के समय भारत की साक्षरता लगभग 20 प्रतिशत के आस–पास थी। आज शिक्षा के प्रचार–प्रसार के चलते 73 प्रतिशत पहुँच गयी है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल 10 प्रतिशत 18 से 23 वर्ष के युवा वर्ग शिक्षा ग्रहण कर रहे है। विश्व स्तर पर यह 22 प्रतिशत के करीब है। वर्तमान में भारत के 2/3 विश्वविद्यालय तथा 90 प्रतिशत महाविद्यालय गुणवत्ताके मानक बिन्दु से बहुत नीचे अपना कार्य निष्पादन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। योजनाएँ बनाना और उनका पालन करवाना यू0जी0सी0 और सरकार का काम है पर सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करने में निरन्तर विफल साबित हुई। तकनीकन पाठयक्रम की शुरूआत तो हो गयी लेकिन शिक्षकों की कमी तथा बुनियादी सुविधाओं को घोर अभाव में पाठयक्रम नहीं बल्कि मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य के भी पाठयक्रम जुझ रहे हैं। विश्वविद्यालय का व्यवस्था तंत्र जो शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच कड़ी है इन्हें गैर शिक्षक कर्मचारी कहा जाता है। ये एक तरह से नाकारात्मकता के शिकार होते है जो इनकी कुण्ठा से जुड़ा हुआ है। गैर शैक्षणिक वर्ग के भीतर यह सोच काम करता है कि ये कहीं न कहीं से हीन है इसलिए इनका रवैया शिक्षण या शिक्षक विरोधी हो जाता है। शिक्षा केन्द्रों को शिथिल करनें में इनकी प्रमुख भूमिका होती है।

21वीं सदी के प्रारम्भ में भारत की शिक्षित युवा पीढ़ी ने सूचना और संचार तकनीक के क्षेत्र में उसे अत्यंत सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया है। विकसित नई कार्य संस्कृति के तहत भारत की वैधानिक तथा तकनीकी क्षेत्र की क्षमताओं को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भरपूर सराहना मिल रही है। सारा विश्व आज भारतीयों के ज्ञान समाज के निर्माण में किये जाने वाले योगदान से अभीभूत है। आजादीके समय भारत की साक्षरता लगभग 20 प्रतिशत के आस–पास थी। आज शिक्षा के प्रचार–प्रसार के चलते 73 प्रतिशत पहुँच गयी है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल 10 प्रतिशत 18 से 23 वर्ष के युवा वर्ग शिक्षा ग्रहण कर रहे है। विश्व स्तर पर यह 22 प्रतिशत के करीब है। भारत के सामने यह समस्या है कि अपनी आर्थिक विकास दर बनाये रखने के लिए उसे 20–22 प्रतिशत तक लाना जरूरी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में त्वरित योजनाओ को लागू करें। भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओ की कमी के कारण लगभग 80 हजार युवा प्रतिवर्ष विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने चले जाते है। वही भारत में बाहर से उच्च शिक्षा के लिए विधार्थियों की संख्या 8 हजार के आस पास है।

सरकार को उच्च शिक्षा के न सिर्फ संस्थान बढ़ाने हैं बल्कि उसी गुणवत्ता को भी श्रेष्ठ स्तर पर लाना हैं। वर्तमान में भारत के 2/3 विश्वविद्यालय तथा 90 प्रतिशत महाविद्यालय गुणवत्ताके मानक बिन्दु से बहुत नीचे अपना कार्य निष्पादन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों मे व्यापक बदलाव की आवश्यकता हैं। तभी हमारे युवा ज्ञान और कौशल के क्षेत्र में विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा मे अपना स्थान बना पायेगें। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता कौशलों में कमी एक बड़ी असफलता का बिन्दु हैं। इस दृष्टि से उच्च शिक्षा में युवा वर्ग की विश्वविद्यालयों की ग्लोबल रैंकिग में जब भारतीय विश्वविद्यालयों का नाम नही दिखायी देता,तो समूचा देश भारत की उच्च शिक्षा के बारे में आत्मग्लानि महसूस करता है। कभी–कभी इन ग्लोबल रैंकिगों में आई•आई•टी• या आई•आई•एम• के नाम दिखायी देते हैं तो हमे खुशी होती हैं कि कम से कम इंजीनियरिंग और प्रबन्ध शिक्षा में तो हमारी पहचान विश्वस्तरीय हैं। उच्च शिक्षा में हमारी शिखर संस्थाए चमकती दिखायी देती है,लेकिन उच्च शिक्षा के पिरामिड में धरातल पर आने वाले बहुसंख्यक विश्वविद्यालय और कालेज बेरौनक होते जा रहे हैं। बहुसंख्यक युवाओं को दाखिला देने वाले इन संस्थाओं पर सवालिया निशान गहरे होते जा रहे हैं।

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा विभाग), एस0एन0 सेन बालिका पी0जी0 कालेज, कानपुर

देश में उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों में 58 प्रतिशत निजी क्षेत्र में अनुदानित या गैर अनुदानित संस्थानों में पढ़ते हैं और सिर्फ 42 प्रतिशत सरकारी संस्थानों के विद्यार्थी हैं अधिकांश प्राइवेट कालेज राज्यों के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होते हैं और इनके प्रवेश, पाठयक्रम व परीक्षायें उन्हीं विश्वविद्यालयों व कालेजों में पढ़ने वाले कुल 80 लाख विद्यार्थियों में से सिर्फ 6 प्रतिशत (पांच लाख) केन्द्र सरकार द्वारा पोषित संस्थानों में पढ़ते हैं। बाकी 94 प्रतिशत (75 लाख) राज्यों के विश्वविद्यालयों या कालेजों में शिक्षा पाते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के रूपान्तर में उच्च शिक्षा के महत्व को कम करके नही आंका जा सकता हैं। आने वाले दशकों मे अगर हमें विश्व स्तर पर अमेरिका और चीन का मुकाबला करना है तो उच्च शिक्षा में कुछ बुनियादी करने होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2020 तक 20–24 वर्ष के आयु वर्ग में भारत में 11.6 करोड़ और चीन में 9.4 करोड़ श्रमिक व कर्मचारी होंगे। 2020 में भारत की औसत आयु 29 वर्ष होगी और 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में हमारी 60 प्रतिशत आबादी होगी। अगर हम विश्व स्तर पर चीन और अमेरिका का मुकाबला चाहते हैं तो हमें उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी होगी। सिर्फ केन्द्रीय विश्वविधालयों और केन्द्रीय संस्थानों को मजबूत बनाने से यह सम्भव नही होगा। हमें राज्य के विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों की हालत में समुचित सुधार होगा।

आज के दौर में 316 राज्य विश्वविद्यालय और 13024 अनुदानित कालेज जिस संकट का सामना कर रहे हैं उसका मुख्य कारण उन्हें मिलने वाले वित्तीय अनुदान का लगातार कम होते जाना। पिछली 3 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व संस्थानों को मिलने वाले वित्तीय अनुदान तेजी से बढ़े है वही दूसरी और राज्य विश्वविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान उतनी तेजी से नही बढ़े हैं। 9वी पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को मिलने वित्तीय अनुदान 2272 करोड़ रूपये से बढ़ कर 34787 करोड़ रूपये हो गया। जो कि लगभग 15 गुना था । दूसरी ओर राज्य विश्वविद्यालयों को मिलने वाला अनुदान 1724 करोड़ रूपये से सिर्फ तीन गुना बढ़ कर 5342 करोड़ रूपये हो पाया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उच्च शिक्षा समिति ने अपनी एक रिर्पोट में कहा है–'उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता में कभी नतीजतन फीस बढ़ाने के उपाय और उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की तीब्र बढ़ोत्तरी, उच्च शिक्षा की उपलब्धता, गुणवत्ता, समानता और कार्य कुशलता के लिए गम्भीर समस्या पैदा कर रही है।

इसके लिए राज्य सरकारें भी कम दोषी नही है। पूरे देश में राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 5 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा पर खर्च होता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड जैसे राज्यो का सफल नामांकन अनुपाद भी कम है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड जैसे राज्यों का सकल नामांकन अनुपात भी कम है। और उच्च शिक्षा पर प्रतिशत खर्च भी कम है। दूसरी ओर तमिलनाडू ,आन्ध्र प्रदेश,केरल,गोवा,त्रिपुरा जैसे राज्यों का प्रति विद्यार्थी व्यय और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) दोनो राष्ट्रीय दौसत से बेहतर हैं। नौकरशाही व लालफीताशाही भी राज्य विश्वविद्यालयों के वित्तीय संकट को बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2021) के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों की खस्ता हालत को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार ने 22891 करोड़ का वित्तीय अनुदान दिया गया। जिसमें से सिर्फ 7652 करोड़ रूपयें ही खर्च हो पाना सह जाहिर कहता है कि राज्य विश्वविधालयों में अनुदान के उपयोग की तत्परता का अभाव है। और प्रक्रियायें काफी जटिल हैं।राज्यों विश्वविधालय सिर्फ वित्तीय संकट का ही सामना नही कर रहे, बल्कि राजनैतिक हस्ताक्षेप, सम्बद्ध कालेज प्रणाली का बोझ अनुभव अकुशल प्रशासन जबावदेही के अभाव और निरंकुश नौकरशाही जैसी समस्यायें भी इन्हें निष्प्रभावी बना रही हैं।

उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर हमारे देश के राष्ट्रपति और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रणव मुखर्जी भी चिन्तित हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई और अपनी चिन्ता जाहिर की। वास्तविक स्थित को जानने के लिए वे स्वयं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गये। वहां के शिक्षकों और छात्रों से मिले। इसी क्रम में राष्ट्रपति जी से एक विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में कहा कि ''हमें ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा,जहां युवाओ को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरू‍प शिक्षा

मिले, उन्होंने छात्रों में आत्मचेतना,सम्बेदनशीलता, मौलिक सोच विकसित करने और प्रभावशाली संवाद,समस्या समाधान व अन्तवैयक्तिक सम्बन्ध दक्षता बढ़ाने की जरूरत है''।

केवल शिक्षा के बजट को बढ़ाने भर से शिक्षा को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि उन बुनियादी कारणों की खोज की जाय और उन कारणों के समाधान का भी सार्थक प्रयास किया जाय। हमें जमीनी स्तर पर उच्च शिक्षा को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए ईमानदारी से आगे आना पड़ेगा। विद्यालयी पढ़ाई करने वाले नौ छात्रों में से एक छात्र ही कालेज पहुँच पाता है। उच्च शिक्षा हेतु पंजीकरण कराने वालों का अनुपात हमारे यहाँ दुनिया में सबसे कम 11 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में सह 83 प्रतिशत है। उस अनुपात को 15 प्रतिशत तक ले जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत को 226410 करोड़ रूपये का निवेश करना होगा, जबकि 11वीं योजना में इसके लिए केवल 77933 करोड़ रूपये का ही प्रवाधान किया गया था। उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। योजनाएँ बनाना और उनका पालन करवाना यू0जी0सी0 और सरकार का काम है पर सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करने में निरन्तर विफल साबित हुई। तकनीकन पाठयक्रम की शुरूआत तो हो गयी लेकिन शिक्षकों की कमी तथा बुनियादी सुविधाओं को घोर अभाव में पाठयक्रम नहीं बल्कि मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य के भी पाठयक्रम जुझ रहे हैं।

विश्वविद्यालय केवल कुछ शैक्षणिक भवनों का समूह नहीं होता है, बल्कि वह एक ऐसा केन्द्र हैं जहाँ विचार और चेतना की सीमा को गहन शोध, प्रयोग और विवेचना द्वारा हमेशा विस्तार देने का प्रयास किया जाता हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान के मुख्यतः तीन अंग होते हैं–शिक्षक शिक्षार्थी और गैर शैक्षणिक कर्मचारी। किसी भी संस्थान की सफलता और विफलता इन्ही पर निर्भर होंती हैं। सबसे पहले शिक्षक की भूमिका की बात करें, शिक्षक ज्ञान के विकास और प्रसार के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने का सामाजिक अभिकर्ता होता है। सामान्य यह है कि शिक्षक समुदाय अपनी सामूहिक जिम्मेदारी अथवा कर्तव्य परायणता से विमुख हो रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि निर्धारित पेशे में आपेक्षित दक्षता प्राप्त करने पर भी उन्हें यह विश्वास नही रहता कि उनका हक उनकों मिलेगा। आज जिस तरह का माहौल है उसमें कोई भी अध्यापक केवल अध्ययन–अध्ययन और अनुसंधान में दक्षता के आधार पर पदोन्नति के प्रति आश्वस्त नही रह पाता, और पाया यह जा रहा है कि अयोग्य व्यक्ति केवल जी हुजूरी और चाटुकारिता आदि के दम पर पदोन्नति और महत्वपूर्ण पदों को हासिल कर लेता हैं।

विद्यार्थियों की स्थिति और भी विकट है, लोक तांत्रिक और समतावादी नारों के बावजूद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दुर्दशग्रस्त हैं। सर्वशिक्षा अभियान और मिड–डे मील की असफलता हम सभी के समक्ष है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के जेहन को कुंद कर रहे हैं साथ ही उनके भीतर मौजूद कुशलता को भी खत्म कर रहे हैं। इसी अधकचरी मनोदशा को लेकर उच्च शिक्षा में जाता है जहाँ प्रायः उसे भी मालूम नही रहता कि वह यह शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहता है। हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में वह किसी तरह उत्तीर्ण हो जाता है। यह निराशवादी माहौल उच्च शिक्षाकेन्द्रों को विश्वस्तरीय स्थान दिलाने में असफल हो रहा है और उच्च शिक्षा केवल अर्थ शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही हैं।

निष्कर्ष :–

विश्वविद्यालय का व्यवस्था तंत्र जो शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच कड़ी है इन्हें गैर शिक्षक कर्मचारी कहा जाता है। ये एक तरह से नाकारात्मकता के शिकार होते है जो इनकी कुण्ठा से जुड़ा हुआ है। गैर शैक्षणिक वर्ग के भीतर यह सोच काम करता है कि ये कहीं न कहीं से हीन है इसलिए इनका रवैया शिक्षण या शिक्षक विरोधी हो जाता है। शिक्षा केन्द्रों को शिथिल करनें में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। ऐसे माहौल मे हम चिन्तन और शोध की संभावना कैसे कर सकते है। इन्ही सब कारणों से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, एस0पी0 (2006), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, इलाहाबादःशारदा पुस्तक भवन
2. सारस्वत, मालती, एस0एल0 गौतम (2006), भारती शिक्षा का विकास एवं सामाजिक समस्यायें, लखनऊ : आलोक प्रकाशन
3. अदावल, सुबोध, एम0 डनियाल (1982), भारतीय शिक्षा की समस्याएँ तथा प्रवृत्तियाँ, लखनऊ : उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
4. गुप्ता, एस.पी. और अलका गुप्ता, 2008, 'भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याए' इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन
5. मलहोत्रा, पी.एल. एवं अन्य, भारत में विद्यालयी शिक्षा : वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताएं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद परिषद, अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली
6. भारत सरकार, शिक्षा की चुनौती (1985): नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय
7. रिसर्च एबस्ट्रेक्स (2009–10) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ, उ.प्र.